दैनिक जागरण
जीवन में समस्याएं नहीं, सिर्फ चुनौतियां हैं

फिर से राफेल का राग

विधानसभा चुनावों के सिलसिले में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी सभाओं को संबोधित करने निकले राहुल गांधी राफेल सौदे में कथित दलाली की चर्चा जिस तरह फिर से कर रहे हैं उससे यही लगता है कि उन्होंने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय से कोई सबक नहीं सीखा। लोकसभा चुनावों के पहले उन्होंने इस मुद्दे को तूल देने के साथ ही चौकीदार चोर है का नारा भी उछाला था, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। आम धारणा यही है कि इस नारे ने उलटा असर किया, लेकिन शायद राहुल गांधी अभी भी यह मान रहे हैं कि राफेल सौदे में दलाली के आरोप को लगातार उछालने से वह सही साबित हो जाएगा। वह राफेल सौदे को संदिग्ध बताने के साथ ही अपने इस पुराने आरोप को भी नए सिरे से धार देते दिख रहे हैं कि मोदी सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से किसी की भी असहमति हो सकती है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि उद्योगपतियों को चोर साबित करने की कोशिश की जाए। दुर्भाग्य से राहुल यही कर रहे हैं। महाराष्ट्र की एक रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंबानी और अदानी का लाउडस्पीकर तो बताया ही, मोदी सरकार की तुलना जेब काटने वालों से भी कर दी। ऐसा करते हुए उन्होंने तू-तड़ाक वाली भाषा का भी इस्तेमाल किया। आखिर ऐसी भाषा के इस्तेमाल के बाद कांग्रेस के नेता विरोधी दलों को भाषा की मर्यादा में रहने की नसीहत कैसे दे सकते हैं?

राहुल गांधी जीएसटी को भी फिर से गब्बर सिंह टैक्स बताने में जुट गए हैं। इससे कुछ पता चल रहा है तो यही कि वह ऐसे नेता नहीं जो अपनी गलतियों पर गौर करें। अभी हाल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी अपने हिसाब से राजनीति करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें यह भी देखना चाहिए कि पार्टी किस दिशा की ओर बढ़ रही है? यह अपेक्षा इसलिए, क्योंकि खुद कांग्रेस के ही कई नेता यह कह रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी की जीत के आसार नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं, चुनाव नतीजे क्या बयान करेंगे, लेकिन इससे इन्कार नहीं कि कांग्रेस की दशा दयनीय दिख रही है। शायद ही कोई राज्य ऐसा हो जहां पार्टी गुटबाजी से ग्रस्त न हो। इससे भी खराब बात यह है कि यह जानना कठिन हो रहा है कि कांग्रेस अपने पक्ष में कैसा विमर्श खड़ा करना चाह रही है? राहुल गांधी कुछ भी दावा करें, इसमें संदेह है कि उनके चुनावी भाषण कांग्रेस को एक जिम्मेदार दल के तौर पर उभारने का काम कर सकेंगे।

औली में जगी उम्मीद

उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में शीतकालीन खेलों की मान्यता पर छाए संकट के बादल अब छंटने लगे हैं। प्रदेश सरकार के अनुरोध पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आइओए) ने भी एफआइएस को औली की ढलानों (स्लोप) का निरीक्षण कर इसे अंतरराष्ट्रीय स्कीइंग के लिए स्वीकृति देने के लिए पत्र लिखा है। अब जल्द ही फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कीइंग (फिस) औली का सर्वेक्षण करेगा। उम्मीद है कि नवंबर में खत्म होनी वाली मान्यता का नवीनीकरण तय समय तक हो जाएगा। इसके कोई दो राय नहीं कुदरत ने औली को नेमतें बख्शी हैं। यही वजह है कि हर साल यहां हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। इसके अलावा देश में शीतकालीन खेलों का प्रमुख केंद्र भी है। औली में 1300 मीटर लंबा व 45 मीटर चौड़ा स्लोप और स्लोप पर 1250 मीटर वर्टिकल ड्रॉप है। स्की स्लोप तक पहुंचने के लिए स्की लिफ्ट भी है। इसके अलावा खिलाड़ी, आयोजक, पर्यटक व दर्शकों के रहने के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। स्नो मेकिंग मशीन भी यहां लगी है और सड़क बंद होने की स्थिति में रोपवे से औली पहुंचा जा सकता है। वर्ष 2010 में औली की ढलानों को फिस ने शीतकालीन खेलों के लिए पूरी तरह फिट मानते हुए इसे 2019 तक मान्यता दी। जब यहां पहली बार वर्ष 2011 में इंटरनेशनल सैफ गेम्स आयोजित हुए तो औली देश-दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन गया, लेकिन इसके बाद यहां इस स्तर की कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जा सकी। वजह यह कि औली से मानो कुदरत रूठ गई। कम बर्फबारी के कारण वर्ष 2012 में इंटरनेशनल फिस रेस और वर्ष 2014 में जूनियर नेशनल गेम्स दो बार रद करने पड़े। इसकी मुख्य वजह रही सीजन में औली में पर्याप्त मात्रा में बर्फबारी की कमी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मामला इतना ही है। देखा जाए तो इसमें कुछ न कुछ लापरवाही आयोजकों की ओर से भी रही है। प्रतियोगिता के आयोजन का वक्त ज्यादातर फरवरी अथवा मार्च में तय किया गया। फरवरी व मार्च में ढलानों पर नाममात्र की बर्फ ही मिली। ऐसे में आयोजन संभव नहीं था। पहले भी यह सवाल उठता रहा है कि जब दिसंबर आखिर अथवा जनवरी में मौसम मेहरबान रहता है तो प्रतियोगिता का आयोजन तभी क्यों नहीं करा लिया जाता। सिक्के का एक और पहलू यह है कि तैयारियों के नाम पर आयोजक भी मुस्तैद नजर नहीं आते। स्नो मेकिंग मशीन खराब रहती है। मशीन की मरम्मत को लेकर अधिकारी शायद ही कभी गंभीर रहे हों।

भारत के खिलाफ उभरता नया गठजोड़

ब्रिगेडियर आरपी सिंह

तुर्की, मलेशिया जैसे देश पाकिस्तान का समर्थन कर जब दोस्ताना रिश्तों का गलत फायदा उठाने लगें तो हमें भी उन पर शिकंजा कसना चाहिए

कश्मीर पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने में नाकाम रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को तुर्की, मलेशिया और चीन से जो समर्थन मिला वह डूबते को तिनके का सहारा जैसा है। मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत को निशाना बनाया। बीते कई दशकों में यह किसी गैर-पाकिस्तानी नेता के इस मुद्दे पर सबसे तल्ख तेवर थे। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को एक देश बताया जहां भारत ने घुसपैठ की। महातिर ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की अनदेखी उसके प्रति अनादर और कानून तोड़ने वाली है।' साफ है कि उन्हें यह पता ही नहीं कि जम्मू-कश्मीर कोई देश नहीं, बल्कि ब्रिटिश भारत में एक रियासत थी और उसके शासक ने भारत के साथ विलय की संधि की थी। वास्तव में पाकिस्तान ने आक्रमण करके कश्मीर के हिस्से अवैध रूप से कब्जा लिए। महातिर का भारत को आक्रांता और कश्मीर को देश बताना यही दर्शाता है कि या तो उन्हें गलत जानकारी दी गई या बढ़ती उम्र के साथ उनकी बुद्धि उनका साथ नहीं दे रही है।

अगर 1965 के भारत-पाक युद्ध को छोड़ दें तो घरेलू राजनीतिक-धार्मिक दबावों के चलते मलेशिया ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। मलेशिया की 61.3 प्रतिशत जनसंख्या सुन्नी मुसलमानों की है और पाकिस्तान की तरह यहां की बहुसंख्यक आबादी इस्लाम की सलाफी और वहाबी विचारधारा को मानती है। महातिर उस पख्तान हरप्पन (पीएच) गठबंधन के मुखिया हैं जिसने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी नजीब रजाक सरकार को सत्ता से बेदखल कर जीत हासिल की। पीएच के अधिकांश घटक मुस्लिम बहुल दलों के हैं जो इस्लामिक शरीया कानूनों का समर्थन करते हैं। कश्मीर पर अपनी टिप्पणियों से महातिर ने रूढ़िवादी मलय मुसलमानों की खुशामद का प्रयास किया है।

संयुक्त राष्ट्र में महातिर के भाषण से पहले मोदी ने उनसे मुलाकात कर उन्हें अनुच्छेद 370 का मुद्दा समझाया। मोदी ने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की मांग भी रखी जिस पर महातिर पहले ही अपनी टांग अड़ा चुके थे। मलेशिया की सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता रही है। भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्रीय खिलाड़ी है जो मलेशिया का संतुलन बिगाड़ सकता है। 2018-19 में भारत ने मलेशिया से 10.8 अरब डॉलर का आयात और मलेशिया को 6.4 अरब डॉलर का निर्यात किया। इसकी तुलना में मलेशिया-पाकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार तकरीबन 1.3 अरब डॉलर है। भारत मलेशिया से हर साल 2.5 अरब डॉलर का पाम ऑयल आयात करता है। यदि इसे वह इंडोनेशिया या अन्य देशों से आयात करना शुरू कर दे मलेशिया को बड़ा झटका लगेगा। सुखोई विमानों के रखरखाव से लेकर मलेशिया के साथ कई रक्षा सहयोग परियोजनाएं चल रही हैं। कुआलालंपुर भारत को पुराने मिग-29 विमान बेचना चाहता है। यह सौदा भी खटाई में पड़ सकता है। हालांकि द्विपक्षीय रिश्तों के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। मलेशिया की कुल आबादी में आठ प्रतिशत हिस्सेदारी भारतीय मूल के लोगों की है। उन्हें मलेशिया के तमाम क्षेत्रों में बराबरी का दर्जा हासिल है।

अवधेश राजपूत

महातिर की तर्ज पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र संबोधन में कहा था कि 'आठ लाख कश्मीरियों को एक तरह से कैद रखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।' इस मुद्दे को तवज्जो न देने के लिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी खूब खरीखोटी सुनाई। तुर्की पाकिस्तान का पुराना और वफादार दोस्त है। वह पाक के गठन के बाद उसे मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था। पाक को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दिलाने में भी तुर्की ने पूरा सहयोग किया। दोनों देश शीत युद्ध के समय सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेंटो वाले पश्चिमी गठजोड़ के सदस्य थे। 1955 में इसकी स्थापना ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और ब्रिटेन द्वारा की गई थी और 1979 में इसे भंग कर दिया गया। तुर्की ने 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को अपने विमान और अन्य रक्षा साजोसामान की मदद मुहैया कराई थी। उसने हमेशा पाकिस्तान के उस रुख का समर्थन किया है जिसमें पाक संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराने पर जोर देता आया है। नवंबर 2016 में पाकिस्तान दौरे में वहां की संसद को संबोधित करते हुए एर्दोगन ने यही दोहराया था। तुर्की एनएसजी में पाक को शामिल कराने का समर्थक रहा है।

कश्मीर पर एर्दोगन का बयान चीन में प्रताड़ना केंद्रों में रखे गए दस लाख से अधिक उइगर मुसलमानों पर साधी गई चुप्पी के एकदम उलट है। जबकि बीते एक साल तक वह इस मुद्दे को पूरी सहानुभूति के साथ उठाते थे। तुर्की इकलौता मुस्लिम-बहुसंख्यक आबादी वाला देश है जिसका उइगर-तुर्किश नस्लीय समूह से सीधा ताल्लुक है। मानवाधिकारों के मसले पर तुर्की का अपना रिकॉर्ड भी बेहद खराब है। तुर्की की 20 फीसद आबादी कुर्दों की है जिनका बीती दो सदियों से दमन किया जा रहा है। कुर्दिश भाषा, संस्कृति, गाने, संगीत और यहां तक कि कुर्दिश नाम भी प्रतिबंधित हैं। उन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा तक नहीं मिला और उन्हें कुर्दिश पहाड़ी लोग कहा जाता है। कश्मीर को लेकर एर्दोगन की टिप्पणियों के बाद संयुक्त राष्ट्र में मोदी ने ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे तुर्की के प्रतिद्वंद्वी देशों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। ये बैठकें तुर्की को यह सख्त संदेश देने के लिए ही की गईं कि वैचारिक मुद्दों के बजाय वास्तविक मसले ही कूटनीतिक दिशा तय करते हैं।

महातिर मोहम्मद, एर्दोगन और इमरान खान मुस्लिम जगत के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया को दूर करने के लिए साझा पहल पर सहमति जताई है, लेकिन किसी ने भी चीन में उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर कुछ नहीं कहा। भारत जहां तीन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला बड़ा देश है जबकि पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की की अर्थव्यवस्थाएं मिलाकर भी एक ट्रिलियन डॉलर की नहीं हैं। जब छोटे-मोटे देश दोस्ताना रिश्तों का गलत फायदा उठाने लगें तो नई दिल्ली को भी उन पर अपना शिकंजा निश्चित रूप से कसना चाहिए।

चीन के लिए अपने आर्थिक साम्राज्यवादी एजेंडे को सिरे चढ़ाने में पाकिस्तान बहुत उपयोगी है। इस कड़ी में शी चिनफिंग की महत्वाकांक्षी बीआरआइ परियोजना के लिए चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा किसी जीवनरेखा से कम नहीं। पाक की चीन पर हद से ज्यादा निर्भरता शी के सपने को साकार करने में सहायक बनी है। बीजिंग के लिए पाकिस्तानी आतंक भारत के खिलाफ एक बड़ा हथियार है। इमरान के हालिया बीजिंग दौरे में कश्मीर पर शी की आश्वस्ति से यह एक बार फिर पुष्ट हुआ। चीन को यह याद दिलाना होगा कि शीशे के घर में बैठकर वह भारत पर पत्थर नहीं फेंक सकता। भारत को इस पर भी ध्यान देना होगा कि चीन, तुर्की और मलेशिया जैसे परंपरागत दोस्तों की मेहरबानी से ही पाक एफएटीएफ की काली सूची में जाने से बच रहा है।

(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

कर्ज के नाम पर लुटते बैंक

राजीव सचान

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि बैंक अभी भी रिजर्व बैंक से सूचनाएं छिपाने में लगे हुए हैं

हीरा कारोबार के नाम पर हेराफेरी करने वाला नीरव मोदी अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ बीते साल की शुरुआत में देश से बाहर भाग गया था। इन दोनों की फरारी के कुछ समय बाद यह सामने आया कि उन्होंने किन बैंकों से कितना कर्ज ले रखा था। सबसे ज्यादा चूना लगा पंजाब नेशनल बैंक को। पहले बताया गया कि इन मामा-भांजे ने पंजाब नेशनल बैंक से करीब 10 हजार करोड़ रुपये की ठगी की है, लेकिन फिर जब कुछ और बैंकों ने खुद को ठगे जाने की सूचना दी तो डूबी रकम बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गई। इसके बाद रिजर्व बैंक भी सक्रिय हुआ और भारत सरकार भी। रिजर्व बैंक ने आनन-फानन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नियमन संबंधी नियम बदले और यह प्रतीति कराई कि अब सब कुछ नियंत्रण में आ गया है, लेकिन यह सच नहीं था और इसका प्रमाण मिला पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से दी गई इस सूचना से कि 44 करोड़ रुपये न चुकाने वाले मेहुल चोकसी को विल्फुल डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है। विल्फुल डिफॉल्टर यानी कर्ज चुकाने में मक्कारी करने वाला। सरकारी क्षेत्र के बैंक ऐसे मक्कार कर्जखोरों से त्रस्त हैं। इनमें से तमाम विदेश भाग गए हैं। इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ बढ़ रही है एनपीए की राशि। एनपीए यानी फंसा हुआ कर्ज। बैंक एक सीमा के बाद इस फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डालने को मजबूर होते हैं।

कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बैंकों का एनपीए कम हो रहा है, लेकिन इन खबरों का आधार फंसे कर्जों की वसूली कम, बल्कि उन्हें बट्टे खाते में डालना अधिक है। यह खबर पिछले हफ्ते ही आई है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पिछले तीन वर्षों में 2.75 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बट्टे खाते में डाल दिए। इन बैंकों में सबसे अव्वल रहा भारतीय स्टेट बैंक जिसने दो सौ से अधिक डिफॉल्टरों के 76,600 करोड़ रुपये के कर्ज बट्टे खाते में डाले। जिनके फंसे कर्ज बट्टे खाते में डाले गए उन पर सौ करोड़ रुपये या इससे अधिक लोन बाकी था। लगता नहीं कि यह सिलसिला थमने वाला है। रिजर्व बैंक की तमाम चौकसी और सरकार की सख्ती के बाद भी बैंकों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले कभी चाकू की नोक पर बैंक लूटे जाते थे वैसे ही अब लोन के नाम पर बैंक लूटे जा रहे हैं। विडंबना यह है कि जो जितना बड़ा कर्जदार होता है उसके खिलाफ कार्रवाई उतनी ही मुश्किल होती है।

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि बैंक अभी भी रिजर्व बैंक से सूचनाएं छिपाने में लगे हुए हैं। क्या यह संभव है कि पंजाब एंड सिंध बैंक को पिछले हफ्ते ही यह पता चला हो कि मेहुल चोकसी नामक कारोबारी 44 करोड़ का कर्ज चुकाने में आनाकानी कर रहा है? आखिर इस बैंक ने तभी इस बारे में क्यों नहीं बताया जब मेहुल के देश से भाग जाने की खबर आई थी? क्या बैंक अधिकारियों को यह भरोसा था कि मेहुल भाई समय पर कर्ज चुका देंगे?

ये वे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार के साथ ही रिजर्व बैंक को भी देने होंगे। सरकार और रिजर्व बैंक को सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली को लेकर भी जवाब देने होंगे, क्योंकि पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक के खाताधारक सड़क पर हैं। सब जानते हैं कि नोटबंदी के समय ही यह सामने आ गया था कि सहकारी बैंक नियम-कानूनों की अनदेखी करने में कहीं आगे हैं। कायदे से तभी इन बैंकों का नियमन दुरुस्त करने के कदम उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों नहीं किया गया? अब जब पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक घपलेबाजी का शिकार हो गया तब सरकार के साथ रिजर्व बैंक की आंखें खुली हैं। वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है कि सहकारी बैंकों के नियमन की खामियों पर रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के अधिकारी जल्द ही चर्चा करने वाले हैं।

आखिर यह चर्चा इसके पहले क्यों नहीं की गई? यह सवाल इसलिए, क्योंकि यह पहली बार नहीं जब किसी सहकारी बैंक में गड़बड़ी के चलते खाताधारक प्रभावित हुए हों। बीते दो सालों में अकेले महाराष्ट्र में कम से कम पांच सहकारी बैंकों की वित्तीय गड़बड़ियों के चलते रिजर्व बैंक उन पर पाबंदियां लगाने को मजबूर हुआ है। समझना कठिन है कि जब इन सहकारी बैंकों की गड़बड़ियां सामने आ रही थीं तब किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आया कि उनके कामकाज को दुरुस्त करने के लिए कुछ करने की जरूरत है? निःसंदेह सवाल यह भी है कि सहकारी क्षेत्र के बैंक रिजर्व बैंक के वैसे ही अधिकार क्षेत्र में क्यों नहीं हैं जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? क्या इसलिए, क्योंकि सहकारी बैंकों पर नेताओं और उनके रिश्तेदारों का कब्जा है? यह ठीक है कि सरकार ने यह समझा कि सार्वजनिक क्षेत्र में इतने अधिक बैंकों की जरूरत नहीं और उसने उनके विलय का फैसला किया, लेकिन क्या यह सही समय नहीं कि वह इस पर भी विचार करे कि क्या देश को इतने अधिक सहकारी बैंकों की जरूरत है?

आखिर उनकी संख्या घटाने की जरूरत क्यों नहीं समझी जा रही है? सहकारी बैंक कर्ज देने के नाम पर किस तरह खुद को खुशी-खुशी लुटवा रहे हैं, इसका ही उदाहरण पेश किया है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक ने। उसने एचडीआइएल नामक एक ऐसी कंपनी को कर्ज दे दिया जो अपना पिछला कर्ज नहीं चुका पाई थी। यह अंधेरगर्दी के साथ-साथ एक तरह की खुली लूट है। अगर इस तरह की लूट जारी रही तो बैंकों के साथ-साथ रिजर्व बैंक और सरकार के लिए अपनी साख बचाना मुश्किल होगा। इससे इन्कार नहीं कि बैंकों की खराब स्थिति का एक कारण मनमोहन सरकार के दौरान बरती गई ढिलाई है, लेकिन अगर मोदी शासन के पांच साल बाद भी बैंकिंग व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है तो यह चिंता की ही बात है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

हंसना-मुस्कुराना

हंसना एवं मुस्कुराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका एकमात्र अधिकार मानव को ही प्राप्त है। विद्वानों का मानना है कि जब व्यक्ति हंसता-मुस्कुराता है तो ईश्वर की आराधना कर रहा होता है और जब वह दूसरों को हंसाता है तब ईश्वर उसकी आराधना करते रहते हैं। मेडिकल साइंस भी मानता है कि हंसने से तमाम बीमारियां दूर होती हैं। एक सर्वे में यह तथ्य पाया गया है कि हंसने का सर्वाधिक उपयोग नवजात शिशु करते हैं। साल-दो साल के बच्चे सोते रहते हैं फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। लगभग छोटी-बड़ी मुस्कुराहट मिलाकर वे तीन-चार सौ बार मुस्कुराते हैं। छोटे बच्चों की सुंदरता का राज यही मुस्कुराहट है। ज्यों-ज्यों वे बड़े होने लगते हैं और सांसारिक प्रभाव की चपेट में आते हैं तब सबसे पहले उनकी मुस्कुराहट गायब होने लगती है जिसके गायब होने से उनकी लावण्यता कम होने लगती है।

सवाल है कि जन्म से प्राप्त हंसी क्यों गायब हो जाती है। इसके पीछे वजह भौतिक कारणों के साथ आसपास के परिवेश में लिप्त हो जाना ही है। नकारात्मक जीवनशैली से तो इतना प्रभाव पड़ता है जिसकी कल्पना प्रायः आम आदमी नहीं कर पाता। जबकि कोई ऐसी वस्तु जिसे पाने की कोशिश की गई, नहीं हासिल हुई तो भी प्रसन्न मन से पुनः प्रयास करना चाहिए। इससे निराशा नहीं होगी। भगवान श्रीराम को अयोध्या की गद्दी की जगह जंगल मिल गया फिर भी वे विचलित नहीं हुए। प्रायः चित्रों में भगवान को मुस्कुराते हुए चित्रित किया गया है। इसका आशय ही है कि जहां मुस्कुराहट है वहां भगवान हैं। जबकि दैत्यों के चित्रों में तनाव, क्रोध दिखाया जाता है। यदि कोई तनाव में है तो इसका अर्थ उसके आसपास से भगवान हट गए हैं और दैत्य आ गए हैं। इसलिए सुख हो या दुख हर स्थिति को झेलने की शक्ति सकारात्मक सोच से ही हासिल की जा सकेगी। वास्तविक हंसी के लिए सुबह जगने से लेकर रात सोने तक सिर्फ भौतिकता में डूबे रहने से बचना होगा। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन से हंसी गायब हो जाए।

सलिल पांडेय

राहत के इंतजार में बैंक उपभोक्ता

अनीश कुमार

जब तक बैंक घटे ब्याज दर पर कर्ज नहीं देंगे तब तक घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ाई जा सकेगी

आरबीआइ ने रेपो रेट में अब तक 1.35 फीसद की कटौती कर चुका है। इतना ही नहीं आरबीआइ के गवर्नर ने रेपो रेट में और कटौती की संभावना जताते हुए कहा है कि इसका निचला स्तर क्या हो अभी हमने यह तय नहीं किया है। लगातार गिर रहे रेपो दर से होम लोन एवं ऑटो लोन की ब्याज दर में गिरावट आ रही है, पर बाजार तेजी नहीं पकड़ पा रहा है। आरबीआइ की यह चिंता रही है कि आर्थिक सुशासन को कैसे पटरी पर लाया जाय। इसी के चलते वह लगातार रेपो दर में कटौती करता रहा। सरकार ने भी सितबर में कॉरपोरेट टैक्स को 10 फीसद घटाकर आर्थिक सुस्ती को दूर करने की कोशिश की है।

आरबीआइ जानता है कि खपत एवं विकास दर को गति देने से ही आर्थिक सुधार और प्रगति संभव है। ऐसे में उसका मुख्य मकसद मौद्रिक नीति की न केवल समीक्षा करना, बल्कि आर्थिक प्रगति के रास्ते को भी चौड़ा करना है। मगर आर्थिक प्रगति के पूरे तानेबाने के बीच कौन रोड़ा है, इसकी भी पहचान जरूरी है। रेपो दर में कटौती का सीधा फायदा ऋण धारकों को क्या बिना किसी प्रयास के मिल रहा है? क्या बैंक आरबीआइ की इस गाइडलाइन को ईमानदारी से लागू करने में पारदर्शी रवैया अपना रहे हैं? देखा गया है कि आरबीआइ के रेपो दर में गिरावट के बावजूद बैंक ऋण दर में कटौती नहीं करते हैं जिसके चलते आरबीआइ का आर्थिक सुशासन वाला पक्ष खतरे में बना रहता है।

हालांकि तकरीबन सारे बैंक अपनी कर्ज की दरों को रेपो रेट से लिंक कर चुके हैं। बावजूद इसके ग्राहकों से सौ रुपये का स्टांप पेपर और हस्ताक्षर की मांग करते हैं। इसकी पूर्ति के बाद ही ऋण दर में कटौती संभव होती है। बीते कुछ वर्षों से बैंक कई आर्थिक कारणों के चलते एनपीए में फंसे हैं और यह अनुपात 10 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है जो बीते पांच वर्षों में दोगुना हुआ है। एनपीए में फंस चुके बैंकों ने इससे बाहर निकलने के लिए अपने नियमों में हेर-फेर किया है। जिसका सीधा नुकसान आम खाताधारक के हिस्से दिखाई देता है। बैंकों ने स्वयं को उबारने के लिए सामान्य खाताधारकों की जेब पर डकैती डाला यह कहना भी अतार्किक न होगा। नए नियम और विनियम के चलते मनमानी तरीके से खाता से पैसा निकालकर बैंक अपना घाटा पूरा करने लगे हैं।

बहरहाल मौजूदा समय में रेपो रेट की इतनी दर इसके पहले दिसंबर 2010 में थी तब यह 5.15 फीसद के स्तर पर थी। उन दिनों भी देश में आर्थिक मंदी की स्थिति थी और इससे बाहर निकलने के लिए आरबीआइ ने ब्याज दरों में भारी कटौती की थी। मगर सवाल वही है कि जिस मकसद से आरबीआइ रेपो दर में गिरावट कर रहा है क्या उसका फायदा सीधे आम लोगों को मिल रहा है? पड़ताल बताती है कि पिछले साल से मौद्रिक समीक्षाओं में रेपो दर में जितनी गिरावट लाई गई है, उसका पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं मिला है। साफ है कि जब तक बैंक घटे ब्याज दर पर कर्ज नहीं देंगे तब तक घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

सर्वत्र चलते हैं बहुसंख्यक तौर-तरीके

'अज्ञानता से उपजा विरोध' शीर्षक से लिखे अपने लेख में हृदयनारायण दीक्षित ने अत्यंत तार्किक तरीके से हिंदू पद्धति के अनुसार की गई राफेल-पूजा के विरोध की हवा निकाली है। सेक्युलरिज्म जिस पश्चिम की उपज है, वहां बहुसंख्यकों के कर्मकांड या तौर-तरीकों को मिली मान्यता भारतीय सेक्युलरों को विस्मृत कर देगी। ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष (राजा अथवा रानी) की उपाधि (धर्म-रक्षक, डिफेंडर ऑफ द फेथ) है। यानी उसका कार्य ब्रिटिश राज्य-धर्म 'एंग्लिकन चर्च' की रक्षा करना है। वहां राजा या रानी या उनका दांपत्य साथी सिर्फ 'एंग्लिकन चर्च' को मानने वाला ही हो सकता है। इसीलिए राजा एडवर्ड अष्टम को 1938 में गद्दी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि वह एक रोमन कैथोलिक महिला वालिस सिंपसन से ही विवाह करना चाहते थे। प्रधानमंत्री बाल्डविन इस बात की अनुमति देने को भी तैयार नहीं हुए कि सिंपसन की संतान गद्दी की वारिस होगी। ब्रिटिश संसद का सत्र 'एंग्लिकन चर्च' के प्रधान आर्चबिशप ऑफ केंटनबरी की प्रार्थनाओं से प्रारंभ होता है। सभी सरकारी आयोजनों की भी यही स्थिति है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एंग्लिकन पादरियों की एक बड़ी संख्या सदस्य के रूप में सदा मौजूद रहती है। 1941 में अटलांटिक घोषणापत्र जारी होने से पूर्व जहाज पर मौजूद ब्रिटिश पीएम चर्चिल एवं अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने बाइबिल के अनुसार प्रार्थना की थी। पश्चिम इन तमाम ईसाई कर्मकांडों के बावजूद सेक्युलर बना रहता है। भारत में वही हैसियत हिंदू धर्म की है। पं. नेहरू ने यह बात स्वीकार की थी, जब उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व और भारतीयता के बीच अधिक अंतर नहीं है, बल्कि दोनों एक-दूसरे को ढंके रहते (ओवरलैप किए) रहते हैं। अतः वर्तमान कांग्रेस के नेता राफेल-पूजा को विवाद बनाना बंद करें। भारतीय सेना में धार्मिक नारे-राजा रामचंद्र की जय, जय महाकाली आदि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। सेना की हर यूनिट के साथ एक पुजारी या धर्माचार्य की नियुक्ति की जाती है। इस तथ्य को भी याद रखें।

अजय मित्तल, मेरठ

आम जनता भी रखे अपनी बात

देश में एक बार फिर चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष अपने-अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन चुनाव के दौरान तीसरे दल यानी जनता को भी अपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर पैरवी करनी चाहिए। किसी भी चुनाव में तीन दल होते हैं पक्ष, विपक्ष और जनता। जनता के मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिन्हें वे झेल रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर के लोग बीते कुछ सालों से प्रदूषण से बेहाल हैं। प्रदूषण की वजह लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हर समस्या का समाधान है, बस जरूरत है गंभीरतापूर्वक उस पर काम करने की। इसी तरह दूसरा बिंदु है लोक ऋण। सभी प्रदेश सरकारें कर्ज में डूबी हुई हैं। जो भी नई सरकार पदस्थ होती है वह जनता से तरह-तरह के वादे करती है, लेकिन पिछले दरवाजे से आम जनता पर ही कर्ज चढ़ा देती है। हर जन का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस बात को समझे कि उनका प्रदेश कितना कर्ज कब और क्यों ले रहा है और उसकी अदायगी के लिए उपाय क्या हैं। आखिर लोक ऋण अप्रत्यक्ष रूप से जनता के ऊपर ही है। जिस तरह आम जनता को कर्ज देने के लिए सीमा और कुछ शर्त निर्धारित है, उसी तरह से लोक ऋण के लिए भी कुछ शर्तों को लागू किया जाना चाहिए। देश में चीजों को महत्वपूर्ण तभी समझा जाता है जब वह चुनावी मुद्दा बने। आम जनता और राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय और लोक ऋण रोकने के उपाय संबंधित बिंदुओं को चुनाव में शामिल करें और उससे संबंधित वादे करे।

ऋषि भारद्वाज, नोएडा

भारत के लिए गर्व की बात

प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिलना गरीबी उन्मूलन के प्रति उनके संकल्प को दर्शाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को आधार बनाकर गरीबी दूर करने का एक्सपेरिमेंट मॉडल बनाने के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन के बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले और दूसरे भारतीय हैं। मौजूदा समय में पूरी दुनिया में भारतीय अर्थशास्त्रियों का डंका बज रहा है, ऐसे समय में बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिलना इस सोच को और आगे बढ़ाता है। बनर्जी जेएनयू में जब छात्र थे तभी उनके प्रोफेसरों का मानना था कि वह एक दिन दुनिया के लिए कुछ बड़ा करेंगे और उन्होंने कर के दिखा भी दिया।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।